4. The company would agree for certification of their seed plots before supplying the seed to farmers.

5. The proposed new undertaking shall be established outside the standard urban area limit, as determined in the Census of India, 1981, of a city having a population of more than one million.

OR

Outside the municipal limit of a city of population of more than 0.5 million is determined in the Census of India, 1981.

6. The proposed project cost of Rs. 340 lakhs shall be met by the applicant company entirely from its internal resources.

7. The import of capital goods and means of financing thereof shall be subject to the satisfaction of Government.

8. The foreign exchange requirements shall be met by the company with the prior approval of the ECB Division of the Department of Economic Affairs (Ministry of Finance).

9. The company shall comply with the directives issued by the RBI under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

10. Adequate steps shall be taken to the satisfaction of the Government to prevent air, soil and water pollution. Further, the anti-pollution measures to be taken must conform to the effluent and emission standards prescribed by the State of Andhra Pradesh.

उचित दर की दुकानों पर घटिया किस्म के खाद्यान्न की बिक्री

849. **श्री रशीद मसूद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर की दुकानों का दौरा करने की शक्ति प्रदान किए गए स्वैच्छिक संस्थाओं ने यह सूचना दी है कि इन दुकानों के माध्यम से घटिया किस्म का गेहूं, चावल और चीनी बेची जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने भी एक प्रतिवेदन में यह बताया है कि जब इन शिकायतों को खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के ध्यान में लाया गया तो यह उत्तर दिया गया कि इन शिकायतों को क्षेत्रीय अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उचित-दर-दुकानों के माध्यम से घटिया किस्म के अनाज आदि की सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं और बढ़िया क्वालिटी के अनाज, आदि की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या इस तरह की लापरवाही के लिए किसी क्षेत्रीय निरीक्षक और खाद्य और संभरण अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) ये शिकायतें खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन को भेजी गई थीं ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि घटिया क्वालिटी के खाद्यान्नों के बारे में उनके ध्यान में जो लाए गए मामलों की संख्या नगण्य है । स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ने इन विनिर्दिष्ट वस्तुओं की खराब क्वालिटी

का पता लगाने के लिए एक व्यापक प्रणाली तैयार करने हेतु जानकारी (फीड बैक) देने का कार्य किया है । उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जनता को घटिया क्वालिटी के खाद्यान्न की आपूर्ति को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :—

1. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सप्लाई की जाने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुओं की क्वालिटी की अचानक जांच करना ।

2. उचित दर की दुकानों से खराब क्वालिटी के खाद्यान्न मिलने के 72 घंटों के अन्दर रिपोर्ट, यदि कोई हो, स्वीकार करना ।

3. दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 7 दिनों के भीतर घटिया स्टाक को बदलना ।

4. खाद्य और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से परिवीक्षा तथा जांच करना ।

5. सभी 44 मंडलों में एक नियंत्रण कक्ष तथा शिकायत काउंटर खोलना ।

(घ) जी नहीं ।

Strike By C.P.W.D. Jr. Engineers

850. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the workers of C.P.W.D. went on strike in the month of June, 1987;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether it is also a fact that the Junior Engineers of C.P.W.D. went on strike in the month of July, 1987;

(d) if so, what are the details in this regard;

(e) whether it is a fact that the strike has been declared illegal under the Essential Services maintenance Act;

(f) whether the strike was declared illegal in both the cases only after the workers/Junior engineers had already gone on strike; and

(g) the reasons for which the strike was not declared illegal before they went on strike?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The workers of C.P.W.D. owing allegiance to the C.P.W.D. Mazdoor Union had resorted to an illegal strike w.e.f. 23-6-87. The strike was called off by the Union unilaterally on the night of 29-6-87 and the striking workers reported to duty w.e.f. forenoon of 30-6-87.

(c) and (d) Yes. The Junior Engineers of C.P.W.D. are on indefinite strike from 14-7-87.

(e) Yes.

(f) and (g) The C.P.W.D. Mazdoor Union had resorted to strike while the conciliation proceedings were continuing before the Regional Labour Commissioner (Central). Any strike commencing while such conciliation proceedings are on, is illegal under the provisions of Sec. 23(a) of the Industrial Disputes Act, 1947. The essential Services Maintenance Act was also invoked in their case on 26-6-87. As regards the Junior Engineers of C.P.W.D., the Junior Engineers Association was advised to refrain from going on the proposed strike since they are Government servants covered by the Central Civil Services (Conduct) Rules which prohibit the Central Government servants from resorting to any form of strike. According to a notification issued under ESMA by the Administrator of Union Territory of Delhi on 26-6-87, a strike in any service in CPWD/PWD (Delhi Administration) has been declared illegal. A notification under ESMA banning strike in C.P.W.D. throughout the country was also issued by the Ministry of Home Affairs on 17-7-87.